मंडी से शुरू होगा ग्रीन अकाउंटिंग प्रोजेक्ट

योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य होगा हिमाचल

सराहनीय

- नौ माह में वनों से होने वाले लाभ का होगा आकलन
- विश्व बैंक प्रतिनिधियों ने बताए वनों से मिलने वाले लाभ

वन विभाग द्वारा ग्रीन अकाउंटिंग के संबंध में मंगलवार को शिमला में वर्ल्ड बैंक के पदाधिकारियों से विचार-विमर्श करते अधिकारी।

राज्य ब्यूरो, शिमला : वनों से जुड़ा ग्रीन अकाउंटिंग प्रोजेक्ट के लिए प्रदेश सरकार ने मंडी जिले का चयन किया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत नौ महीने में वनों से होने वाले लाभ का आकलन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने ग्रीन अकाउंटिंग की दिशा में पहल की है। इसके तहत वाटरशैड, पराग्रण (पॉलिनेशन) व सिल्ट में कमी को देखा जाएगा।

अभी तक यह माना जाता था कि वनों से लकड़ी, बिरोजा व अन्य औषधियां प्राप्त होती हैं। यह पता नहीं चल पाता था कि वनों से सरकारी महकमों को कितनी आमदनी होती है। इसमें वनों से वायु, जल व दूसरे फायदों को भी इंगित किया जाएगा। ग्रीन अकाउंटिंग के लिए आयोजित सेमिनार के दूसरे दिन टॉलैंड स्थित वन विभाग के मुख्यालय में अधिकारियों को विश्व बैंक प्रतिनिधि उर्वशी नारायण, जुआन पाब्लो व हरिप्रिया ने वनों से मिलने वाले लाभों के बारे में बताया। प्रत्येक अधिकारी के साथ परस्पर सवाल-जवाब हुए।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2013 में वन संपदा के सही आकलन की जरूरत को समझा। इसे समूचे विश्व को भी समझाने के लिए वन संपदा का आकलन करने का निर्णय लिया गया। इसी कड़ी में भारत में भी काम शुरू किया गया है। सरकार प्रदेश में करीब 1.50 लाख करोड़ रुपये की वन संपदा होने का दावा करती है। वनों का संरक्षण करने के लिए सालाना एक हजार करोड़ रुपये देने का मामला भी उठाया गया है। तर्क दिया गया था कि वनों को बचाने व इनका संरक्षण करने के लिए कर्मचारियों व अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। इनके वेतन पर हर साल करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। केंद्र सरकार वायु, जल के संरक्षण की एवज में कुछ भी देने को तैयार नहीं है।

सभी जिलों में होगी अकाउंटिंग

मुख्य वन अरण्यपाल राजीव कुमार का कहना है कि मंडी जिले से तैयार होने वाले अकाउंट्स के बाद बाकी जिलों में भी अकाउंटिंग का कार्य होगा। तभी सही तरीके से पता चल पाएगा कि किस जिले में कितनी वन संपदा है।

अभी तक हुआ आकलन

अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल वित्त सुरेंद्र कुमार पॉल कहना है कि अभी तक तो इस बात का अंदाजा नहीं है कि वन हमारे लिए कितने कीमती हैं। ये माना जाता है कि जंगलों से लकड़ी निकालकर खाना पकाते हैं और वन शुद्ध हवा देते हैं।

कमाई का पता नहीं चलता

आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग में आर्थिक सलाहकार प्रदीप चौहान ने कहा कि वनों पर सरकार के अधिकांश विभाग निर्भर करते हैं। विभाग कमाई अपने खाते में डालते हैं, जबकि उस कमाई का सही मायनों में पता चलना चाहिए।